

था। सरकार सी० एफ० काउन को वलन वलन परियोजना के परामर्शदाता नियुक्त करने के बारे में समिति की सिफारिशों से मुख्य रूप से इस आधार पर सहमत नहीं थी क्योंकि उनको भारत में किसी संयंत्र के निर्माण अथवा संचालन का कोई अनुभव नहीं था, प्रौद्योगिकी के स्थानान्तरण के बारे में जबकि संयंत्र का केवल एक ही सैट दिया जाये, उनका उत्तर संदिग्ध था और उनके द्वारा दिये गये ठेके का प्रस्ताव कानूनी दृष्टि से उपयुक्त नहीं था।

कुछ आवश्यकताएँ हैं। फिर भी दूसरी जगहों से आवश्यकतापूर्वक सप्लाय की व्यवस्था कर कमी को पूरा करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ख) और (ग). डीजल की कमी को पूरा करने के लिए तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(1) इसके आयात को अधिकतम मात्रा में बढ़ाया गया है।

(2) और अधिक टैंक बैगनों को प्रयोग में लाकर रेल परिवहन में सुधार किया गया है, माल और यात्रियों आदि की सेवाओं की अपेक्षा इन बैगनों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है।

(3) तेल कम्पनियों द्वारा सड़क परिवहन का अधिकतम मात्रा तक बढ़ाना।

(4) राज्य सरकारों को डीजल के सम-वितरण को सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

(5) चोरबाजारी, जमाखोर्ग में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध चोर-बाजारी और आवश्यक वस्तु सप्लाय अनुरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को प्रयोग में लाया जा रहा है।

(6) तेल कम्पनियों को अपने फुटकर बिक्री केन्द्रों के पर्यवेक्षण को सख्त करने की सलाह दी गई है।

ईरान-ईराक युद्ध के कारण भारत में तेल के आयात पर प्रभाव

355. श्री हरिकेश बहादुर :

श्री चिरंजीलाल शर्मा :

क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईरान-ईराक के बीच लगातार युद्ध के कारण भारत सरकार द्वारा तेल के आयात पर क्या प्रभाव पडा है ;

(ख) डीजल की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ग) डीजल की चोर बाजारी रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) :

(क) ईरान-ईराक युद्ध के फल-स्वरूप हमारे खनिज तेल के आयात